

जल से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम

इस मॉड्यूल में शामिल विषय हैं –

- भारत सरकार की जल से संबंधित योजनाएं
- यूनेस्को के जल संबंधी कार्यक्रम
- जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका

मॉड्यूल के उद्देश्य

- प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं को निम्न मॉड्यूल उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हैं :
- प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल का अध्ययन।
- जल संसाधन के विकास के मुद्दे पर काम कर रहे मुख्य भारतीय निकायों के बारे में जानना।
- यूनेस्को द्वारा चलाए जा रहे जल से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का अध्ययन।
- जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को समझना।

भारत सरकार की जल संबंधी योजनाएं

जल खाद्य सुरक्षा और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत चीज है। बढ़ती हुई जनसंख्या और तेजी से शहरीकरण के कारण, विभिन्न प्रयोजनों, अर्थात्, घरेलू और नगर निगम की जरूरतें, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, नेविगेशन और औद्योगिक उपयोग आदि के लिए जल की मांग बढ़ी है। वर्तमान में हमलोगों के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं – जैसे कम हो रही प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता, जल की गुणवत्ता में क्षरण, भूजल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर का कम होना, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पूरा होने में लगने वाला समय और लागत तथा मौजूदा सुविधाओं का खराब रखरखाव, जल से संबंधित प्रा.तिक आपदाएं यानी बाढ़ और सूखा आदि। इसके अलावा, यहां जल की उपलब्धता में बड़े अस्थायी और स्थानिक भिन्नता की स्थिति देखने को मिलती है। जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में प्रारंभिक अध्ययन से संकेत मिलते हैं कि जल चक्र के विभिन्न घटकों के प्रभाव के

परिणामस्वरूप जल की उपलब्धता में अस्थायी और स्थानिक भिन्नता की स्थिति और तेजी से आगे बढ़ेगी। यह स्थिति उपलब्ध जल संसाधनों के संरक्षण और कुशल उपयोग के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी की दिशा में तत्काल कदम उठाने के लिए इंगित करती है।

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार अपने मंत्रालयों, विभागों और आयोगों के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करती रहती है। ये योजनाएं केन्द्रीय, राज्य विशिष्ट या केंद्र व राज्यों के बीच संयुक्त सहयोग से चलने वाली होती हैं।

नीचे प्रमुख मंत्रालयों, विभागों, सुप्रीम निकायों, केंद्रीय स्तर पर इन विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने वाली संस्थाओं और विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने और इसे प्रसारित करने वाले पोर्टलों की सूची है।

- केन्द्रीय भूजल बोर्ड (www.cgwb.gov.in)
- केंद्रीय जल आयोग (www.cwc.gov.in)
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (www.dst.gov.in)
- भूजल रिसर्च एंड मैनेजमेंट (gwrmsubscribe@yahoo.com)
- वैश्विक जल भागीदारी (www.gwpforum.org)
- जल विज्ञान फोरम – टोपिका (hydrology-forum-subscribe@topica.com)
- जल विज्ञान फोरम – याहू (hydforum-subscribe@yahoo.com)
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (www.imd.gov.in)
- एकीत जल प्रबंधन संस्थान (www.iwmi.cgiar.org)
- एकीत जल प्रबंधन कार्यक्रम (www.dolr.nic.in/iwmp_main.htm)
- इंडिया वाटर पोर्टल (www.indiawaterportal.org)
- सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड (www.iwrfc.org)
- एमईटीएनईटी : एक ई-गवर्नेंस इंटर-आईएमडी पोर्टल (metnet.imd.gov.in)
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (www.mdws.gov.in)
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (www.dod.nic.in)
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (www.envfor.nic.in)
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (www.rural.nic.in)
- जल संसाधन मंत्रालय (www.mowr.nic.in)
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (www.ndma.gov.in)
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (www.ndmindia.nic.in)
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय
([Http://envfor.nic.in/sites/default/files/NRCD/index.html](http://envfor.nic.in/sites/default/files/NRCD/index.html))
- राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (www.nih.ernet.in)
- राष्ट्रीय जल अकादमी (www.nwa.mah.nic.in)
- राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (www.nwda.gov.in)

निर्मल ग्राम पुरस्कार (www.nirmalgrampuraskar.nic.in)
जीईएफ छोटे अनुदान कार्यक्रम (www.sgp.undp.org)
जल विज्ञान परियोजना (www.hydrology-project.gov.in)
जल इतिहास (www.waterhistory.org)
जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण (www.wqaa.gov.in)
जल संसाधन सूचना विज्ञान प्रभाग (www.waterinfo.gov.in)
भारत के जल संसाधन सूचना प्रणाली (www.india-wris.nrsc.gov.in)
विश्व जल संरक्षण (www.worldwaterconservation.org)

भारत की राष्ट्रीय जल नीति

राष्ट्रीय जल नीति भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जल संसाधनों के लिए योजना बनाने और विकास तथा उसके अधिकतम उपयोग को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, सितंबर 1987 में अपनाई गई थी। इसकी 2002 और बाद में 2012 में समीक्षा की गई और अद्यतन किया गया।

यूनेस्को का जल से जुड़ा कार्यक्रम

जल के क्षेत्र में यूनेस्को तीन प्रकार से कार्य कर रहा है:

- नीति प्रासंगिक सलाह के लिए जल विज्ञान।
- सतत विकास की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा और क्षमता निर्माण।
- पर्यावरण स्थिरता प्राप्त करने के लिए जल संसाधन आकलन और प्रबंधन।
- यूनेस्को का जल परिवार एक वैश्विक नेटवर्क है जो संगठन के रणनीतिक लक्ष्यों को लागू करने के लिए एक साथ काम करता है।

अंतरराष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम

वैश्विक स्तर पर एक विज्ञान और शिक्षा कार्यक्रम के रूप में आईएचपी कार्यक्रमों और पहलों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करता है। सभी आईएचपी से संबंधित गतिविधियां आईएचपी के अंतर सरकारी परिषद के माध्यम से की गई अनुशंसा और समन्वय का समर्थन करता है।

आईएचपी का दो कार्यक्रम, फ्रेंड और हेल्प अपने संचालन अवधारणाओं के माध्यम से सभी आईएचपी विषयों के साथ परस्पर संवाद करता है। आईएचपी से जुड़े कार्यक्रम आईएचपी विषयों के विकास और कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं और गतिविधियों के योगदान को कवर करता है और अक्सर संयुक्त और इंटरएजेंसी कार्यक्रम घटकों के साथ आपस में जुड़ा रहता है।

फ्रेंड (लो रिजिम्स फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंटल एंड नेटवर्क डेटा) – एक

अंतरराष्ट्रीय शोध कार्यक्रम है जो क्षेत्रीय स्तर पर आंकड़ा, ज्ञान और तकनीक के आदान-प्रदान के माध्यम से जल वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए क्षेत्रीय नेटवर्क स्थापित करने में मदद करता है ।

ग्राफिक (ग्राउंडवाटर रिसोर्सज अससेस्मेंट अंडर द प्रेशर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड क्लाइमेट चेंज) – यह यूनेस्को की अगुवाई वाली परियोजना है जो भूजल के वैश्विक जल चक्र के भीतर सूचना का आदान प्रदान करता है। इसके साथ ही यह हमारी समझ को इस संदर्भ में विकसित करता है कि कैसे मानव की गतिविधि पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करती है और यह कैसे मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के जटिल दोहरे दबावों का सामना करता है।

जी-वाडी (ग्लोबल नेटवर्क ऑन वाटर एंड डेवलपमेंट इनफार्मेशन इन एरिड लैंड्स) – शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिए इसका प्राथमिक उद्देश्य जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक वैश्विक नेटवर्क तैयार करना है जो एक प्रभावी वैश्विक समुदाय का निर्माण करने के लिए शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सके।

हेल्प (हाइड्रोलॉजी फॉर द एनवायरनमेंट, लाइफ एंड पालिसी) – जल कानून और नीति विशेषज्ञों, जल संसाधन प्रबंधकों और जल वैज्ञानिकों के लिए जल से संबंधित समस्याओं पर एक साथ काम करने के उद्देश्य से ढांचे का निर्माण करना एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन के लिए एक नया दृष्टिकोण है ।

आईएफआई (इंटरनेशनल लड इनिशिएटिव) – यह बाढ़ प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने हेतु एक इंटरएजेंसी पहल है जो बाढ़ से होने वाले लाभों का फायदा उठाते हैं और सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जोखिम को कम करने के लिए बाढ़ के मैदानों का उपयोग करते हैं। सहभागी : विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ), संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (यूएनयू), जल विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईएएचएस) और आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय रणनीति (आईएसडीआर)।

आईएसएआरएम (इंटरनेशनल शेयर्ड एक्विफायर रिसोर्स मैनेजमेंट) – विशेषज्ञ और प्रवीण लोगों के नेटवर्क को स्थापित करने की दिशा में यह एक ऐसी पहल है जो बाउन्ड्री जलवाही स्तर की एक विश्व स्तरीय सूची संकलित करेगा और साझा भूजल संसाधनों के प्रबंधन के विषय में बुद्धिमान प्रथाओं और मार्गदर्शन उपकरण को भी विकसित करेगा।

आईएसआई (इंटरनेशनल सेडीमेंट इनिशिएटिव) – कटाव और समुद्र में बहकर आए तलछट, सतह जल के संरक्षण और निवारण के लिए झील या जलाशय वातावरण को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण का निर्माण, बारीकी से नीति और प्रबंधन की जरूरत के साथ विज्ञान को जोड़ने के लिए सही आकलन करने के उद्देश्य से की गई एक पहल है।

जेआईआईएचपी (जॉइंट इंटरनेशनल आइसोटोप हाइड्रोलॉजी प्रोग्राम) – एक ऐसा कार्यक्रम जो उपकरण के विकास के माध्यम से जल वैज्ञानिक पद्धतियों में

आइसोटोप के एकीकरण की सुविधा उपलब्ध कराता है, आइसोटोप तकनीक को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने और आइसोटोप तकनीकों का उपयोग कर जल संसाधनों के कार्यक्रमों के लिए समर्थन भी करता है।

पीसीसीपी (फ्रॉम पोटेंशियल कनलिकट को ऑपरेशन पोटेंशियल) – एक ऐसी परियोजना जो शांति, सहयोग और विकास के लिए साझा जल संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित बहु स्तरीय और अंतः विषय संवादों को सुविधाजनक बनाता है।

यूडब्ल्यूएमपी (अर्बन वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम) – यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो दृष्टिकोण, उपकरण और दिशानिर्देश के माध्यम से शहरवासियों को अपने ज्ञान में सुधार करने की अनुमति देगा, इसके साथ ही शहर में जल की स्थिति का विश्लेषण और अधिक प्रभावी शहरी जल प्रबंधन रणनीति तैयार करने के लिए तत्पर रहेगा।

डब्ल्यूएचवाईएमपी (वर्ल्ड हाइड्रोलॉजिकल मैप) – वैश्विक स्तर पर भूजल वैज्ञानिक भूजल से जुड़ी जानकारी को जल के मुद्दों पर होनेवाली वैश्विक चर्चा के दौरान उपलब्ध कराते हैं जिससे भूजल से संबंधित परेशानी से मुकाबला किया जा सके।

यूनेस्को-आइएचई

यूनेस्को-आइएचई डेल्ट, नीदरलैंड दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जहाँ स्नातक स्तर की जल शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। नीदरलैंड भागीदारों के सहयोग से पूरी तरह से मान्यता प्राप्त एमएससी डिग्री और पीएचडी की डिग्री प्रदान करता है।

यूनेस्को-आइएचई विकासशील देशों और संक्रमणकालीन देशों में लक्षित समूहों की एक किस्म के लिए सेवाओं की एक विस्तृत रेंज प्रदान करता है : यह शिक्षा, प्रशिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान-जल क्षेत्र के पेशेवरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, सलाहकार और जल व पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत निर्णायकों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

जल क्षेत्र क्षमता विकास – यह खास तौर पर जल क्षेत्र से संबद्ध मंत्रालयों और विभागों, नगरपालिकाओं, जल बोर्डों और पानी उपयोगिताओं, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों, उद्योगों, गैर सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों के लिए है।

भागीदारी निर्माण और नेटवर्किंग – ज्ञान केन्द्रों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के बीच में।

शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मानक स्थापित करना – यह जल के क्षेत्र में जल से संबंधित संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा और प्रशिक्षण एजेंसियों के लिए कार्यरत है।

जल पर नीति फोरम – यूनेस्को के सदस्य देशों और अन्य हितधारकों के लिए।

विश्व जल आकलन कार्यक्रम (डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यूपी)

यूनेस्को के नेतृत्व और मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र विश्व जल आकलन कार्यक्रम (डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यूपी) 28 संयुक्त राष्ट्र-जल के सदस्य देशों और विश्व जल विकास रिपोर्ट (डब्ल्यूडब्ल्यूडीआर) के भागीदारों के मध्य समन्वय का काम करता है।

डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूपी जानकारी, आंकड़ा, उपकरण और प्रभावी नीतियों के विकास में तथा सदस्य देशों को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कौशल के साथ जल प्रबंधकों और महत्वपूर्ण निर्णय करनेवालों को लैस करना चाहता है।

कार्यक्रम के उद्देश्य हैं:

- निगरानी, आकलन और दुनिया के स्वच्छ जल के संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्रों, जल के उपयोग व प्रबंधन पर रिपोर्ट और महत्वपूर्ण मुद्दों तथा समस्याओं की पहचान,
- देशों को खुद का मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करने में मदद करना,
- वैश्विक जल के एजेंडे को प्रभावित करने के लिए वर्तमान और आसन्न/भविष्य में जल से संबंधित चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना,
- निर्णय करनेवालों के लिए जल संसाधनों की जरूरतों का अध्ययन और समाधान प्रस्तुत करना,
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना,
- मजबूत संकेतक के माध्यम से जल संसाधनों के सतत उपयोग को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को मापना, तथा
- वैश्विक जल की व्यवस्था करना व वैकल्पिक भविष्य की पहचान करने के साथ वायदाकारी निर्णय का समर्थन करना।

विश्व जल दिवस के लिए विषय (1994– 2014)

विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 के बाद शुरू हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व जल दिवस शके रूप में 22 मार्च की घोषणा की। अपनी स्थापना के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र-जल विषय के चयन, संदेश और विश्व जल दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के नेतृत्व की जिम्मेदारी लेता है। इसकी स्थापना के बाद से वर्षवार विषयें निम्न हैं –

1993 – शहर के लिये जल

1994 – हमारे जल संसाधनों का ध्यान रखना हर एक का कार्य है

1995 – महिला और जल

1996 – प्यासे शहर के लिये पानी

1997 – विश्व का जलरू क्या पर्याप्त है

1998 – भूमी जल- अदृश्य संसाधन

1999 – हर कोई प्रवाह की ओर जी रहा है

- 2000 – 21वीं सदी के लिये पानी
- 2001 – स्वास्थ्य के लिये जल
- 2002 – विकास के लिये जल
- 2003 – भविष्य के लिये जल
- 2004 – जल और आपदा
- 2005 – 2005–2015 जीवन के लिये पानी
- 2006 – जल और संस्कृति
- 2007 – जल दुर्लभता के साथ मुंडेर
- 2008 – स्वच्छता
- 2009 – जल के पार
- 2010 – स्वस्थ विश्व के लिये स्वच्छ जल
- 2011 – शहर के लिये जलरू शहरी चुनौती के लिये प्रतिक्रिया
- 2012 – जल और खाद्य सुरक्षा
- 2013 – जल सहयोग
- 2014 – जल और ऊर्जा

जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका

‘रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।

पानी गयो ना ऊबरे, मोती मानुष चून।।’

कविवर रहीम ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें जल संरक्षण के महत्व को बताया है, क्योंकि बिना जल के सब कुछ बेजान है य कुछ भी नहीं बढ़ेगा, न तो मोती, न तो मनुष्य और न ही अनाज।



अपने परिवार को पर्याप्त मात्रा में जल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होने के कारण महिलाएं दुनिया भर में जल की मुख्य उपयोगकर्ता रही हैं। कई संस्कृतियों में, महिलाएं और पुरुष जल प्रबंधन में योगदान देते हैं, लेकिन वे अलग अलग तरीकों से ऐसा करते हैं। दोनों समूहों के पास मूल्यवान और पूरक ज्ञान तथा विशेषज्ञता है और इस

तरह दोनों को योजना निर्माण और जल कार्यक्रमों के निष्पादन में शामिल किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल के उपयोग में महिलाओं की विशिष्ट जिम्मेदारियां उन्हें विशेषज्ञता प्रदान करती है। यह सबसे अधिक लागत प्रभावी निर्णय और प्रबंधन की खोज में महत्वपूर्ण है।

परिदृश्य

गाँवों में महिलाएं मीलों लंबी दूरी तय कर अपने परिवार के पीने और सफाई की जरूरत के लिए जल लाती हैं। जल संकट जल प्रदाता के रूप में महिलाओं के लिए एक बढ़ती हुई बोझ में तब्दील हो रहा है और बढ़ते जल की कमी और जल प्रदूषण के साथ, जल से संबंधित रोग देखभाल करने वाले के रूप में महिलाओं पर विषम बोझ में वृद्धि करता है। महिलाओं को जल की कमी और जल प्रदूषण की वजह से असंगत बोझ सहन करना पड़ता है। यद्यपि अतीत में महिलाएं जल संसाधनों के साथ भूमि संसाधनों की संरक्षक और अभिभावक रही हैं, तथापि आज यह जरूरी है कि महिलाओं की भागीदारी जल प्रबंधन में और पर्याप्त जल के प्रावधान सुनिश्चित करने में हो। नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो महिलाओं को वितरण, संरक्षण और उनके क्षेत्र में जल के उपयोग से संबंधित मामलों में निर्णय लेने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे।

प्रमुख महत्व की ये चीजें देखने योग्य हैं :

- महिलाओं को समय और ऊर्जा की कमी की वजह से घर तथा खेतों में जल के स्रोतों के चयन व सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में परेशानी होती है।
- जल लाने में लगने वाले कीमती समय और ऊर्जा लागत से ही महिलाओं के लिए स्वच्छता और रोग की रोकथाम के महत्व की अवधारणा को निर्धारित किया जाता है।
- जल के नियंत्रण का वर्ग और लिंग आयाम महिलाओं के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है।
- जल जनित रोगों से जुड़े मिथ जैसे कि महिलाओं में मूत्र सिस्टोसोमियासिस उनके स्वयं के स्वास्थ्य व्यवहार और स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावित करता है। इसके जैसे अन्य सामाजिक कारक भी रिपोर्टिंग के तहत या महिलाओं में मूत्र सिस्टोसोमियासिस में योगदान करते हैं।
- रोगों के अयोग्यकारी प्रभाव जैसे कि सिस्टोसोमियासिस और गिनी-वर्म की वजह से महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं में उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है।
- यह पूरे परिवार के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति के लिए खतरे की घंटी है।
- समय और सामाजिक दबाव के कारण महिलाएं मलेरिया से ग्रसित हो जाती हैं और उनके उपचार में देरी भी हो जाती है।
- गर्भावस्था के दौरान मलेरिया के विरुद्ध महिलाओं की रोग प्रतिरक्षा क्षमता न्यूनतम होती है इससे महिलाओं और उनके भ्रूण के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उत्पन्न हो जाती है।
- कैडमियम से संपर्क महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस और अन्य हड्डी के रोगों के खतरे को बढ़ा सकता है।

जल संकट लैंगिक समानता के आयाम का प्रतीक है और इसे कम करके आंका नहीं जाना चाहिए है। विकासशील देशों में पानी लाना महिलाओं और बच्चों का काम है। महिलाएं दुनिया की जल वाहक हैं। घंटों पैदल चलकर वे अपने परिवार के लिए दिनोंदिन बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 60 लीटर पानी लाती हैं। इस भार को ले जाने के परिणामस्वरूप उनमें कई स्थायी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऊर्जा और समय के ऐसे व्यय के बाद उनके लिए स्कूल और शिक्षा तथा विस्तार में विकास व आर्थिक आजादी के लिए कोई जगह ही नहीं बचता है। महिलाएं जल ढोकर लाती हैं जबकि पुरुष नीति निर्माता रहे हैं। ये पुरुष ही हैं जो जल के प्राधिकारों को बनाते हैं और पंप के बारे में फैसला करते हैं, कुओं के स्थान और जल के वितरण को तय करते हैं। जल का निजीकरण महिलाओं के खिलाफ सामाजिक भेदभाव को और बढ़ाता है।

क्या किया जाना चाहिए

- महिलाओं को जल के बेहतर उपयोग के लिए जल प्रबंधक के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को जल उपयोगकर्ता के रूप में ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमगगगग/परियोजनाओं को तैयार किया जाना चाहिए।
- जल संरक्षण के तरीकों की मान्यता के लिए पुरस्कार और योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू किया जाना चाहिए।

सीखी गयी बातें



- खाद्य सुरक्षा और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए पानी मौलिक चीज है।
- भारत सरकार अपने मंत्रालयों, विभागों और आयोगों के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न योजनाओं को शुरू करती है।
- यूनेस्को का जल परिवार एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में काम कर रहा है जो संगठन के रणनीतिक लक्ष्यों को लागू करने के लिए एक साथ काम करता है।
- महिलाएं दुनिया भर में मुख्य जल उपयोगकर्ता और अपने परिवार के लिए पर्याप्त जल और साफ-सफाई उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार भी रही हैं।
- गाँव में महिलाओं को मीलों लंबी दूरी तय कर अपने परिवारों के पीने और स्वच्छता के लिए जल लाना पड़ता है।
- महिलाएं जल की कमी और जल प्रदूषण की वजह से असंगत बोझ सहन करती हैं।
- महिलाओं को जल के बेहतर उपयोग के लिए जल प्रबंधक के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को जल उपयोगकर्ता के रूप में ध्यान में रखते हुए कोई कार्यक्रम/परियोजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
- जल संरक्षण के तरीकों को मान्यता दिलाने के लिए पुरस्कार और योजनाएं शुरू की जानी चाहिए।

